



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 703) पटना, बुधवार, 1 जुलाई 2026

सं० 06 सू०प्रा०-23/2026-1191
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

25 जून 2026

विषय:— राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति।

[Approval for signing a memorandum of understanding (MoU) between Axonwise Private Limited (Sarvam) and Department of Information Technology, Bihar, Patna for development of Artificial Intelligence (AI) Ecosystem in the State.]

बिहार सरकार नये-नये तकनीकों का समावेश कर नवाचार के माध्यम से राज्य के विकास हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, 732, अर्बन वॉल्ट इंदिरानगर, 732, चिन्मय मिशन हॉस्पिटल रोड, 1st स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलोर-560038), भारत में स्थित विश्व की अग्रणी तकनीकी कंपनियों में से एक है, जो क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, जेनरेटिव एआई एवं डिजिटल कौशल विकास में विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता रखती है। एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच एक नीतिगत गैर-वित्तीय एवं गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने का प्रस्ताव है।
3. प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग करेंगे :—

- राज्य में हर नागरिक और सरकारी अधिकारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की पहुँच को सुलभ एवं आसान बनाना तथा एआई के बेहतर उपयोग और विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
 - भारत में बने बुनियादी (Fundamental) एआई मॉडल्स और एप्लिकेशन्स तक राज्य के विभागों की पहुँच सुनिश्चित करना।
 - बिहार के स्वीकृत शोधकर्ताओं को भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में अपनी एआई रिसर्च क्षमताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाना।
 - स्थानीय भाषाओं में स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजकर, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एआई संचालित शासन के मॉडल के रूप में स्थापित करना।
 - सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एक स्थानीय भागीदार इकोसिस्टम तैयार करना ताकि लम्बे समय तक एआई विकास को बल मिले।
4. MoU में विभिन्न क्षेत्रों में Pilot परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है, जो प्राथमिकता निर्धारण, व्यवहार्यता मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहमति से क्रियान्वयन होगी। इनमें प्रमुखतः निम्नलिखित संकेतात्मक पहल सम्मिलित है :-
- राज्य में शुरूआती स्तर की एआई नीतियों को बनाने उन्हें लागू करने और सरकारी अधिकारियों को भारत में बने स्थानीय व सॉवरैन एआई सॉल्यूशंस की ट्रेनिंग देने में मदद करेगा।
 - राज्य के विभागीय प्राथमिकताओं, नागरिकों को सेवा देने के लक्ष्यों एवं मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर एआई Strategy तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य के अधिकारियों को एआई के आधुनिक विकास और गवर्नेंस से अवगत कराने के लिए ज्ञान सत्र (Knowledge Sessions) आयोजित करेगा।
 - भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण हेतु अनुकूलित एआई मॉडल, राज्य के प्रमुख भाषाओं जैसे- भोजपुर, मैथिली, मगही एवं अंगिका में वॉयस सपोर्ट, किसानों के लिए कीटों और फसलों की बीमारियों का पता लगाने वाले विशेष विजन मॉडल तथा कानून व्यवस्था के लिए एफआईआर, ड्राफ्टिंग व रियल-टाइम अनुवाद हेतु उन्नत एआई समाधान विकसित किये जायेंगे।
 - कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों के स्थानीय भाषाओं और वॉयस आधारित स्मार्ट एआई टूल्स का उपयोग करके पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ताकि नागरिक सेवाओं और सरकारी कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके।
 - राज्य के स्थानीय इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य द्वारा नामित स्थानीय और राष्ट्रीय तकनीकी भागीदारों को बेंगलुरु में अपने मुख्य प्रोडक्ट (Samvaad, Content Studio, Indus) पर मुफ्त गहन प्रशिक्षण, प्लेटफॉर्म क्रेडिट और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, ताकि राज्य के विभागों के लिए एआई एप्स विकसित किये जा सकें।
 - राज्य सरकार के सूचना प्रावैधकी विभाग को डेटा सुरक्षा, सुप्रभू कम्प्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और जिम्मेदार गवर्नेंस के सिद्धांतों पर आधारित एक सुरक्षित और इनोवेटिव एआई नीति विकसित करने हेतु 'सरवम' सलाहकार के रूप में मदद करेगा।
 - राज्य सरकार के सरकारी अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए एआई ट्रेनिंग एवं कोर्स तैयार करेगा।
5. प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की प्रमुख शर्तें एवं विशेषताएँ निम्नवत् है :-
- यह MoU गैर वित्तीय प्रकृति का है। इसके अंतर्गत किसी पक्ष पर कोई मौद्रिक दायित्व, वित्तीय प्रतिबद्धता, अनुदान, सब्सिडी अथवा बजटीय देनदारी सृजित नहीं होगी।
 - यह MoU प्रभावी तिथि से 60 (साठ) माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
 - दोनों पक्षों की गोपनीय सूचना की पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
 - किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम, पायलट परियोजना, क्रय अथवा अन्य पहल से उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों हेतु पृथक निश्चित समझौता निष्पादित किए जाएंगे, जो दोनों पक्षों की प्रासंगिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन होंगे।
 - एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधकी विभाग, बिहार, पटना, किसी भी वित्तीय दायित्व के लिए Definitive Agreement करेंगे एवं अलग से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

- MoU पर आधारित कोई भी समाचार विज्ञप्ति, सार्वजनिक घोषणा अथवा प्रचार-प्रसार दोनों पक्षों की पूर्व लिखित सहमति के बिना जारी नहीं की जाएगी।
 - MoU भारत के कानूनों के अधीन शासित होंगे तथा किसी भी विवाद का निपटारा पटना स्थित न्यायालयों में किया जायेगा।
6. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
7. उक्त संकल्प को दिनांक 24.06.2026 को मद संख्या-30 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 703-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>